लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2512

06 अगस्त, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

बंगाल में जूट उद्योग

2512. श्री पार्थ भौमिक:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार की, विशेष रूप से मिल संचालन में गिरावट और जूट मिल श्रमिकों के लिए काम की पाली में कमी जैसी हालिया चुनौतियों को देखते हुए बंगाल में जूट उद्योग को सहायता और बढ़ावा देने के लिए वर्तमान नीति संरचना क्या है;

(ख) वार्षिक जूट बिक्री में 3,80,000 गांठों से 1,50,000 गांठ तक की महत्वपूर्ण गिरावट में अंशदान करने वाले कारकों का ब्यौरा और इस प्रवृत्ति को उलटने के लिए विचार किए जा रहे उपाय क्या हैं;

(ग) सरकार, रोजगार स्थिरता और उद्योग उत्पादकता दोनों सुनिश्चित करने के लिए जूट मिल श्रमिकों के कार्य दिवसों और शिफ्टों में सात दिन और तीन शिफ्ट से घटाकर चार दिन और दो शिफ्ट किए जाने का समाधान करने के लिए क्या कदम उठा रही है;

(घ) सरकार का चीनी, प्याज और आलू जैसी वस्तुओं के लिए पारंपरिक जूट बोरियों के स्थान पर पॉलीबैग के उपयोग के बारे में रूख और नीति क्या है;

(ङ) जूट उद्योग पर इसका प्रभाव और पॉली बैग के स्थान पर जूट बैग के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे उपाय क्या हैं; और

(च) सरकार के जूट खरीद और भारतीय जूट किसानों और घरेलू जूट उद्योगों पर बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय संबंधों के प्रभाव के बारे में इसे प्रबंधित और सुदृढ़ करने के आशय का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वस्त्र राज्य मंत्री

(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क) से (ङ) : पश्चिम बंगाल सहित देश के पटसन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने पटसन पैकेजिंग सामग्री (पैकेजिंग वस्तुओं में अनिवार्य उपयोग) अधिनियम, 1987 अधिनियमित किया है, जिसमें कुछ वस्तुओं को पटसन सामग्री में पैक करने का प्रावधान है। कच्ची पटसन और पटसन वस्तुओं की मांग और आपूर्ति की स्थिति के आधार पर सरकार जूट बैग्स में पैक की जाने वाली वस्तुओं के लिए आरक्षण निर्धारित करती है। पिछले छह वर्षों के दौरान, सरकार ने जूट बैग्स में पैकेजिंग के लिए खाद्यान्न और चीनी के लिए क्रमशः 100% और 20% का आरक्षण रखा है।

वस्त्र मंत्रालय और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग नियमित रूप से जूट बैग्स की मांग और आपूर्ति योजना की समीक्षा करते हैं और पटसन क्षेत्र के लिए स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु सप्लाई प्लान के अनुसार जूट बैग्स का ऑर्डर देने के लिए राज्य खरीद एजेंसियों के साथ संपर्क में रहते हैं।

राष्ट्रीय पटसन विकास कार्यक्रम के तहत, सरकार पॉलीबैग की जगह जूट बैग के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए सेमिनार, कार्यशालाएं, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भागीदारी, पब्लिसिटी कैंपेन आयोजित करती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, सरकार ने ऐसे अवेयरनेस कैंपेनों पर 23.94 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

(च): भारत सरकार व्यापार और वाणिज्य सचिव स्तर की वार्ता पर संयुक्त कार्य समूह के प्रासंगिक बायलेट्रल इंस्टिट्यूशनल मैकेनिज्म के तहत द्विपक्षीय व्यापार से संबंधित मामलों पर बांग्लादेश सरकार के साथ नियमित रूप से संपर्क में है। बांग्लादेश से पटसन आयात के मुद्दे पर भी ऐसे मैकेनिज्म के तहत चर्चा की जाती है।

***